

प्रेषक,

विनोद फोनिया

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

पशुपालन विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 27 जुलाई, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य मद के तहत मोथरोवाला, देहरादून में अनावासीय भवन निर्माण हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-23/नि०/भ०नि०/रा०सै०यो०/2010-11 दिनांक 1.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य हेतु मोथरोवाला, देहरादून स्थित विभागीय भूमि पर अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्त विभाग के तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रूपया 429.57 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-924/XV-1/1(17)/2008 दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 के द्वारा रूपया 123.68 लाख प्रथम किश्त, शासनादेश संख्या-3076/XV-1/1(17)/2008 दिनांक 3 नवम्बर, 2009 द्वारा रूपया 50.00 लाख द्वितीय किश्त एवं शासनादेश संख्या-227/XV-1/10/1(17)/08 दिनांक 11 फरवरी, 2010 के द्वारा रूपया 50.00 लाख तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गई। श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में योजना में अवशेष धनराशि के सापेक्ष रु० 100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) चतुर्थ किश्त के रूप में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण पूर्व में स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग के पश्चात ही वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाए।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।
4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि से मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाये।
8. जी०पी०डब्लू० फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
9. स्वीकृत निर्माण कार्यों को तत्काल प्रारम्भ किया जाय ताकि आगणनों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े। निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, तो शासन स्तर से आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्यों को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराई जाये।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-00-101-पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-पशुपालन विभाग में राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-163(P)/XXVII-04/10 दिनांक 23 जुलाई 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या: 1712 (1) / XV-1/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, चकराता, देहरादून।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
9. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ✓ 11. निदेशक, एन०आई०सी० को बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
✓ (जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव